विद्युत वितरण

आईपीडीएस योजना (मासिक आद्यतन जुलाई 2021)

एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) को 20 नवंबर, 2014 को मंजूरी दी गई थी। आईपीडीएस शहरी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर मीटरिंग सहित उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने की परिकल्पना करता है। पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) नामक पिछली योजना को आईपीडीएस की नई योजना में शामिल किया गया है। योजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

क. उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

ख. मीटरिंग

ग. आईटी अनुप्रयोग-ईआरपी और कस्टमर केयर सेवाएं

घ. सौर पैनलों का प्रावधान

ड. आर-एपीडीआरपी के चल रहे कार्यों को पूरा किया जाएगा

अब तक, आईपीडीएस के तहत 31,314 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 15,916 करोड़ रुपये परियोजनाओं के लिए जारी किए गए हैं और 219 करोड़ रुपये गतिविधियों के सक्षमीकरण के लिए जारी किए गए हैं।

पूर्ववर्ती आर-एपीडीआरपी को 44,011 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आईपीडीएस में शामिल किया गया है, जिसमें 12वीं और 13वीं योजना के लिए 22,727 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गई है। आर-एपीडीआरपी के तहत परियोजनाओं को दो भागों में शुरू किया गया है। भाग-क बेसलाइन डेटा की स्थापना के परियोजनातथा ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा एवं एलटी आधारित उपभोक्ता सेवा केंद्रों के लिए एलटी एप्लिकेशन की परियोजना है और भाग-ख नियमित वितरण मजबूत करने वाली परियोजना है। आर-एपीडीआरपी के तहत 31,674 करोड़ रुपये भाग-क (आईटी) के लिए 4522 करोड़ रुपये), भाग-क (स्काडा) के लिए 937 करोड़ रुपये और भाग-ख के लिए 26,215 करोड़ रुपये) की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब तक, आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं के लिए 13,219 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त, 535 करोड़ रुपये गतिविधियों के सक्षमीकरण बनाने के लिए जारी किए गए हैं।